

an&gt;

Title: Need to include development works executed by Zila Panchayat authority under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme.

**श्री शैलेश कुमार )भागलपुर:**( देश में न्यूनतम दर पर मजदूरी करने वाले मजदूरों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। न्यूनतम दर पर वर्ष में कम से कम 100दिन रोजगार मुहैया करने के लिए सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना के अंतर्गत पंजीकृत सभी लोगों को 100दिन का भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है ,इसकी मुख्य वजह महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गतसीमित क्षेत्र में ही रोजगार देने की व्यवस्था का होना है। जब इस योजना की शुरुआत की गई तब ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ही विकास कार्यों में लोगों को रोजगार मिल पाता था ,लेकिन धीरे-धीरे कई विभागों से भी इसे जोड़ा गया है ,फिर भी लोगों को पूर्ण रूप से रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इस परिस्थिति में भारत सरकार को इस योजना के तहत रोजगार उपलब्ध करने के लिए कई स्तर पर इस योजना को जोड़े जाने की आवश्यकता है।

भारत सरकार से मेरी मांग है कि देश भर में जिला पंचायत/जिला परिषद के तहत होने वाली विकास योजनाओं से भी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना को जोड़ा जाए ताकि जिस भी क्षेत्र में विकास योजनाओं को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना से जोड़ा गया है उस कार्य योजना में हर पंजीकृत व्यक्ति को 100दिन का रोजगार मिलना सुनिश्चित हो सके।